रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वेलू): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां, खरीद की प्रक्रिया में लगने वाले समय में कटौती करके, पारदर्शिता लाने, कुशलता में सुधार लाने तथा मांग पत्र भेजने वालों को बेहतर सेवा मुहैया कराने सहित वस्तुसूची पर बेहतर नियंत्रण लाने के लिए रेलवे द्वारा इलैक्ट्रानिक प्रोक्योरमेंट अथवा ई-प्रोक्योरमेंट की एक प्रणाली विकसित की जा रही है, इस प्रणाली से निर्माण संबंधी निविदाओं में माफिया/आपराधिक गतिविधियों में कमी आने की भी संभावना है।

(ख) इलैक्ट्रानिक प्रोक्योरमेंट की उत्तर रेलवे में एक पायलट परियोजना प्रारंभ की जा रही है। इस पायलट परियोजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन और उससे प्राप्त अनुभव के आधार पर इसे और बेहतर करने के पश्चात् इस प्रणाली का अन्य क्षेत्रीय रेलों तक विस्तार किया जाएगा। इस प्रणाली में भंडारों की खरीद, निर्माण, सेवाएं और सामग्रियों की बिक्री जैसी गति-विधियां शामिल की जाएंगी।

(ग) प्रयोग के तौर पर, इलैक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट प्रणाली को प्रारंभ करने का निर्णय पहले ही ले लिया गया है, जिसके लिए 2004-05 के रेलवे बजट में आवश्यक धनराशि की स्वीकृति की मांग की गई है।

Inviting tenders through internet

†*368 SHRIMATI SAVITA SHARDA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state

(a) whether Government propose to invite tenders through internet keeping in view the crimes being committed due to the contractor system in railways,

(b) if so, the details thereof, and

(c) by when a final decision is likely to be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI R. VELU): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir. A system of electronic procurement of E-Procurement is being developed by the Railways to bring about transparency, improved

† Original notice of the question was received in Hindi

efficiency by reduction in procurement time cycle and better control on inventory along with improved service level to indentors. The system is also expected to curtail mafia/criminal activities seen in works tenders

(b) A pilot project on Electronic Procurement is being started in Northern Railway. After successful implementation of this pilot project and fine-tuning of the system on the basis of working experience, the system would be extended to other Zonal Railways. The system would cover all activities like procurement of stores, works,services and sale of materials

(c) The decision to start an Electronic Procurement system on trial basis has already been taken for which necessary sanction of funds has been sought in the Railway Budget, 2004-05

श्रीमती सविता शारदा: धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, ठेका प्रथा के कारण दिन-प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार के बढ़ने के कारण काफी संख्या में अपराधों की बढ़ोत्तरी हो रही है। इसके साथ ही साथ कई बार मर्डर भी हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों में बिहार जाते हुए दो लोगों का मर्डर हो गया है। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें बताया है कि इसके लिए मांग पत्र भेजने वालों को बेहतर सेवा मुहैया कराने वालों के लिए इलेक्ट्रानिक प्रोक्योरमेंट अथवा ई-प्रोक्योरमेंट की प्रणाली विकसित की जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि इस प्रणाली का कब तक विकास होगा? मंत्री जी ने कहा है कि इस प्रणाली से निर्माण संबंधी निविदाओं में आपराधिक गतिविधियों में कमी आयेगी, इसके बारे में, मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि कितनी संख्या में इन गतिविधियों में कमी आयेगी?

SHRI R VELU Sir, the hon Member knows that this system was announced by the hon. Minister of Railways in this Budget We are now working on the system as a pilot project in the Northern Railways. Since we are putting it as a pilot project, we are working on the model and our operating capacity It will take at least two years to complete the whole system As the hon Member has mentioned, I totally agree with her that mafia groups really do all sorts of mischief in terms of submission of tenders, getting contracts, etc To get over this, we are going to have this system of electronic procurement not only for contracts but also for procurement of store materials, which will go a long way to ensure that there is efficiency in the system, so that the procurement time is reduced, the cost is reduced, and we get all the benefits

श्रीमती सविता शारदा: सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि तीन साल तक इसमें होगा। मुझे लगता है कि इसमें तो बहुत देर हो जायेगी, क्योंकि अपराधों की संख्या दिन-प्रति-दिन

बढ़ रही है, इसको देखते हुए तीन साल तक रोकना बहुत मुश्किल काम है। इसमें मुझे लगता है कि भले ही कार पार्किंग हो, इन्होंने दो-तीन वस्तुओं के बारे में बताया है - प्रणाली में भंडारों की खरीद है, निर्माण-कार्य हैं, अलग-अलग तरह की सेवाएं हैं, पार्सल योजना है, यहां तक कि वहां पर रेलवे के जो पार्सल भेजे जाते हैं, उसमें जो ठेका प्रथा दी जाती है, उसमें भी काफी भ्रष्टाचार है। तो मंत्री जी, अगर तीन साल तक करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत काम आगे बढ़ जाएगा। यह तीन साल से कम समय होना चाहिए।

जो मेरा तीसरा प्रश्न था "ग" कि इस संबंध में अंतिम निर्णय कब लिया जाएगा, तो आपने उत्तर में कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट प्रणाली को प्रारंभ करने का निर्णय पहले से लिया गया है। पहले से यानि कब से लिया गया है, यह आपने नहीं बताया है। वर्ष 2004-05 के रेलवे बजट में आवश्यक धनराशि की स्वीकृति की मांग की गई है, तो कितनी धनराशि आप आवंटित करेंगे और कब तक करेंगे?

श्री सभापति: ठीक है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन्स पूछ लिए हैं।

SHRI R. VELU: Well, we will try to expedite matters. I never said three years, I said two years Now, the hon. Member has suggested that matters should be expedited. We have already approved Rs. 3.25 crores and provided Rs 1 75 crores in the Budget for this and, if necessary, additional funds will also be provided. The only point is that this being a pilot project, we will try to work out a sound system so that we have our own system, so that Railways have their own E-procurement system. So, the borrowing system will be restricted till the time we develop our own system as such. We appreciate the feelings of hon. members We will try to expedite matters. And we will shorten the period of two years, we will make it less than two years

*369 [The Questioner (SHRI R P GOENKA) was absent For answer *vide* page 39 *infra*]

Loan licenses for Drugs

*370 SHRI DHARAM PAL SABHARWAL†
SHRIMATI PREMA CARIAPPA

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state.

(a) the number of loan licenses for drugs that have been issued in the country for manufacture of medicines,

† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Dharam Pal Sabharwal